भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6318

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना चरण-I

6318. श्री दिलेश्वर कामैत:

श्री अरुण गोविल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 2026 में पूर्ण होने वाली 'भारतमाला परियोजना चरण-I' की प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से आज तक परिवहन के लिए चालू किए गए 'एक्सेस-कंट्रोल्ड' हाई-स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) पश्चिमी और उत्तरी भारत के औद्योगिक समूहों, विशेष रूप से मेरठ क्षेत्र सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यात्रा समय और संभारतंत्र लागत को कम करने में 'दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे' और 'गंगा एक्सप्रेसवे' के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऊँची चोटियों पर स्थित तीर्थ स्थलों के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने में 'पर्वतमाला' (राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम) की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मेरठ और उसके आसपास के विकासशील औद्योगिक और निर्यात केंद्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतमाला परियोजना चरण-1 को सरकार द्वारा 2017 में देश भर में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, कुल 26,425 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाओं को आवंटित किया गया है और इसमें से फरवरी, 2026 तक 22,223 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। परिचालनरत पहुँच-नियंत्रित राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर (एचएससी)/ एक्सप्रेसवे की लंबाई 2014 में 93 किमी से बढ़कर फरवरी, 2026 तक 3,644 किमी हो गई है।

(ख) दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक पहुँच-नियंत्रित, हाई-स्पीड कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी और उत्तरी भारत में यात्री और माल यातायात के कुशल आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। इस कॉरिडोर से दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय यात्री वाहनों के लिए लगभग 50% (लगभग 25 घंटे से 12-13 घंटे तक) और वाणिज्यिक वाहनों के लिए लगभग 51% (लगभग 32 घंटे से 15-16 घंटे तक) कम होने की उम्मीद है। यह लगभग 16% (1,424

किमी से 1,242 किमी) की यात्रा दूरी में कमी प्रदान करता है, जिससे समग्र मार्ग दक्षता में सुधार होता है।

बेहतर संपर्कता और यात्रा के समय में कमी से गलियारे और इसके प्रभाव क्षेत्रों में माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक (रसद) संचालन को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई रोपवे परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	रोपवे परियोजना/ खंड का नाम	लंबाई (किमी में)	स्थिति/ चरण
1	हिमांचल प्रदेश	बिजली महादेव	2.32	स्थानीय विरोध के कारण परियोजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
2	उत्तराखंड	सोनप्रयाग से केदारनाथ	12.9	इस कार्य को सौंपा जा चुका है
3	उत्तराखंड	गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी	12.4	इस कार्य को सौंपा जा चुका है
4	उत्तराखंड	काठगोदाम- हनुमान मंदिर	14.9	डीपीआर चरण में

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार देश भर में उभरते औद्योगिक और निर्यात केंद्रों की संपर्कता की अपेक्षाओं सहित सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का आकलन करती है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणामों, यातायात की अपेक्षा, संपर्कता की आवश्यकताओं और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एमएनपी) के साथ तालमेल के आधार पर परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

*****